राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील कृषक सम्मेलन सह प्रदर्शनी में संबोधन

17 जनवरी, 2020

लखनऊ

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किसानों के हित में आयोजित प्रगतिशील कृषक सम्मेलन सह प्रदर्शनी में मुझे राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ में आकर बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मैं हमारे युवा एवं तेजस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एवं उनकी टीम के काबिल मंत्रियों का हार्दिक अभिनन्दन करना चाहता हूँ कि उन्होंने जमीनी स्तर पर कृषि के क्षेत्र में भारत सरकार एवं प्रदेश शासन द्वारा किसानो की बेहतरी के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करने में सफलता हासिल की है। मुझे विश्वास है कि इन योजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन से हमारे किसान भाइयों के जीवन में अभूतपूर्व सुधार आयेगा।

यह प्रगतिशील कृषक सम्मेलन किसान भाइयों को कृषि एवं इसके आधुनिकीकरण के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे देश का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हमारे अन्नदाता किसान आत्मनिर्भर ना हो जाएँ। कृषि हमारे जीवन की आधारशिला है। हमारे कृषकों की समृद्धि और खुशहाली देश के विकास का परम सूचक है।

हमारा एकमात्र लक्ष्य किसानों को समृद्ध एवं समर्थ बनाना है। जब तक हमारे देश का गाँव, गरीब, किसान और मजदूर सशक्त नहीं होंगे तब तक देश की पूर्ण समृद्धि संभव नहीं है। इसलिए भारत सरकार ने यह लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2020 तक हम अपने किसानों की आय में वृद्धि करके उसको दोगुना कर देंगे।

हम किसान को अन्नदाता कहते हैं और उसके लिए कुछ करना हम सबका फर्ज है। हम कहते है 'जय जवान जय किसान जय विज्ञान' तो इसका अर्थ है कि जवान, किसान और विज्ञान, ये तीनों हमारे देश को सशक्त बनाने का काम करते हैं।

जब हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो इस खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सबसे अहम भूमिका कृषकों की है और खाद्य आपूर्ति, खेतों से व्यक्ति की रसोई तक अन्न व अन्य खाद्य सामग्री पहुंचने की जो लम्बी श्रृंखला है, उसकी पहली कड़ी हमारा कृषक है।

किसान तभी ज्यादा मात्रा में और गुणवत्तापूर्ण अन्न का उत्पादन कर सकेंगे जब उन्हें विज्ञान का साथ मिलेगा। पूरे देश में कृषकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनायें चल रही हैं, जैसे- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नीम कोटेड यूरिया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नैम) आदि। मुझे खुशी है कि ये योजनाएं हमारे देश के कृषि स्वास्थ्य को पूरी तरह बदल देंगी।

किसान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि खेती हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और हमारे कुल श्रम संसाधन का लगभग 54.50 प्रतिशत खेती एवं इससे जुड़े कार्यकलापों में सलग्न हैं। यह भारतीय अर्थव्यवस्था का विशालतम क्षेत्र है। सकल घरेलू उत्पादों का लगभग 16.1 प्रतिशत कृषि और उससे संबंधित व्यवसायों से आता है।

जहाँ तक कि उत्तर प्रदेश राज्य के भूमि संसाधन का प्रश्न है, यह भारत की सबसे उपजाऊ कृषि भूमि में से एक है। माँ गंगा एवं उनकी सहायक नदियों के घने नेटवर्क ने इसे बेहद उर्वर भूमि बना दिया है।

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। इसकी लगभग 65 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। राज्य की लगभग 166 हेक्टेयर भूमि का उपयोग यानि कुल भूमि का लगभग 69 प्रतिशत खेती के लिए उपयोग किया जाता है। गेहूं, गन्ना सहित विभिन्न प्रकार की फसलों की पैदावार यहाँ पर होती है। चावल, आलू, प्याज, टमाटर, आम, हरी फली, कपास इत्यादि यहाँ की कुछ प्रमुख फसलें हैं।

हम जानते हैं कि हरित क्रांति के फ़लस्वरूप हमने अन्न उत्पादन को कई गुना बढाया है। बढती हुई आबादी एवं बदलते मौसम में बाढ, सूखा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि के कारण अनावश्यक रूप से भारी मात्रा में फसलों को क्षति पहुंची है। हमने श्वेत क्रांति के माध्यम से दुग्ध उत्पादन में भी आत्मनिर्भरता प्राप्त की है। अब हमें कृषि एवं पशुपालन को और अधिक आधुनिक रूप देने की जरुरत है क्योंकि बढती आबादी के मद्देनजर कृषि उत्पादन में और वृद्धि की नितांत आवश्यकता है।

इसके लिए हमें नीली क्रांति की जरुरत पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में नदियों का प्राकृतिक संजाल है। हमें इस अनमोल संसाधन का लाभ उठाने की आवश्यकता है। यह बहुत उपयुक्त है कि सरकार द्वारा किसानों को नीली क्रांति योजना और मत्स्य पालन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पशुपालन, मत्स्यपालन, मधुमक्खीपालन, रेशमकीटपालन कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे हम किसानों की समृद्धि का लक्ष्य आसानी से हासिल कर सकते हैं।

कृषि विकास के लिए कृषि मंत्रालय ने अपने कई विभागों में लाभकारी योजनाओं को लागू किया है, इसमें बजट में बढ़ोत्तरी करके कृषि संबंधित अन्य क्षेत्र जैसे डेयरी उद्योग, पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन आदि को समाहित किया है।

गायों की नई देशी नस्लों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए गोकुल मिशन प्रारंभ हुआ है। जिसमें डेयरी द्वारा कृषक अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और विश्व का 19 प्रतिशत दुग्ध भारत से आता है। उत्पादन की इस गति को हमें निरंतर बरक़रार रखना है। इसके लिए हमें नयी तकनीक का उपयोग करना है।

आप सभी सरकार की सात सूत्रीय नीतियों से अवगत होंगे, जिसमें प्रत्येक बूंद पर अधिक फसल, मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाना, कोल्ड स्टोर और गोदामों की श्रृंखला बढ़ाना ताकि कटा हुआ अनाज बर्बाद न हो। खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से वैल्यू एडीशन करना, कृषि पदार्थों की बिक्री में विकृतियों को दूर करने के लिए ई-प्लेटफॉर्म की शुरूआत, और मिश्रित खेती जैसे- मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी से शहद उत्पादन, मेढ़ पर पेड़ आदि योजनाओं के माध्यम से किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उत्पादन को बढ़ावा देने का सुंदर प्रयास हो रहा है।

साथियो, आज तकनीक का युग है और सभी कृषक भाईयों को तकनीकी ज्ञान का लाभ उठाना चाहिए, जैसे मोबाइल फोन पर ऐप्लीकेशन के जरिए मौसम की सूचना, बीज की जानकारी, ई-पोर्टल द्वारा खरीदारी जैसी चीजें संभव हैं। इसके लिए सभी कृषक भाईयों के पास मोबाइल फोन होना जरूरी है। हमारी सरकार का ऐसा प्रयास है कि कृषि से जुड़ी प्रत्येक योजना के लिए मोबाइल ऐप्लिकेशन बने।

मुझे जानकर बहुत खुशी हुई है कि विकास खंड स्तर पर बीज गोदामों की स्थापना की जा रही है, जिससे कृषकों को एक ही छत के नीचे उन्नतशील बीज, कृषि, रक्षा, रसायन एवं अन्य निवेशों के साथ-साथ कृषकों को नई तकनीक का प्रशिक्षण/जानकारी देने हेतु किसान कल्याण केन्द्र उपलब्ध हैं। आपके प्रदेश में यह योजना वर्ष 2017-18 से चल रही है और अब यह पूरे भारत में लागू की जाएगी।

मुझे बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में 100 किसान कल्याण केन्द्र, वर्ष 2018-19 में 31 किसान कल्याण केन्द्र स्थापित किए गए हैं एवं 2019-20 में 50 किसान कल्याण केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। किसान कल्याण केन्द्र के माध्यम से उस इलाके के कृषकों को कृषि संबंधित तमाम जानकारियां एक ही स्थान पर मिल जाएंगी, जिनसे उनको लाभ होगा।

हम सब यह जानते हैं कि देश में 85 प्रतिशत से अधिक किसान छोटे और सीमांत हैं, जिनके पास बाजार में बेचने लायक फसल कम होती है और खेती-बाड़ी में उनके खर्चे बहुत अधिक होते हैं। इसीलिए सरकार ने इन बाधाओं को दूर करने के लिए और किसानों को मुनाफा बढ़ाने के लिए ई-नैम (e-NAM) की शुरूआत की है। ग्रामीण हाटों को कृषि मंडियों के रूप में विकसित किया गया है।

सरकार का ध्यान किसानों पर है, इसलिए प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा की गयी है। इसके तहत एक साल में प्रत्येक किसान को छः हजार रुपये का अनुदान दिया जा रहा है ताकि वे खेती के लिए उत्तम बीज और खाद खरीद सकें। किसानों की बेहतरी के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में सभी रबी एवं खरीफ की फसलों का न्यूनतम बिक्री मूल्य बढ़ाया गया है।

हमारे लाखों मेहनतकश कृषक भाई ही हमारी अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ हैं। उनकी समृद्धि में ही हमारे देश की समृद्धि निहित है।

ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की भी अच्छी पहल है, जिसमें उन्होंने टॉप स्कीम (TOP-Tomato-Onion-Potato) की शुरूआत की है ताकि इसकी उपलब्धता देश में हो और इसके माध्यम से किसानों को हमेशा विक्रय लाभ भी हो। ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत 500 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं और कृषि लॉजिस्टिक की भी पेशेवर सुविधाएं किसानों को दी जाएंगी।

प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के तहत विपणन संबंधी सहायता के साथ फूड प्रोसेसिंग और वैल्यू एडीशन का प्रावधान है, इससे वर्ष 2019-20 में बीस लाख किसानों को फायदा होगा।

आजकल हर क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्यों की बात होती है। जैविक खेती से हम पर्यावरण को होने वाले नुकसान को न्यूनतम स्तर पर ले जा सकते हैं और कृषि लागत को कम करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। इसको

ध्यान में रखते हुए आज जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और जैविक उत्पादों के लिए बाजार का नेटवर्क तैयार हो रहा है।

जब हम कृषकों के कल्याण के विषय में आगे बढ़ते हैं तो हमको औद्योगिक सुधारों और नई प्रौद्योगिकी से उनको जोड़ने के भी प्रयास करने होंगे। कृषि से उत्पादकता बढ़ाना, किसानों को लाभकारी मूल्य दिलवाना और उनको कृषि संबंधी तकनीकी दक्षता से निपुण करना आदि विभिन्न उपाय हैं, जिन पर सरकार तो सोचती है परंतु इसमें सिविल सोसायटी और किसानों के हित में कार्य कर रहे अन्य संस्थानों का भी योगदान जरूरी है।

आज कल कृषि व्यवसाय को भी उसी परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है, जिस तरह हम अन्य व्यवसायों को देखते हैं। जिस तरह पूरी जानकारी और अच्छे कौशल के अभाव में कोई अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, अच्छा शोधकर्ता या गुरू नहीं हो सकता, उसी तरह कृषि की समस्त जानकारी और नवीनतम तकनीक के बिना कृषि को लाभप्रद व्यवसाय बनाना कठिन है।

इस दृष्टि से राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ में आयोजित प्रदर्शनी में किसानों को उन नयी तकनीकों एवं किसान कल्याण केन्द्रों के विषय में जानने का अवसर मिलेगा जो उन्हें विशेष कौशल से युक्त कर सकते हैं। सरकार की विभिन्न स्कीमों एवं योजनाओं के बारे में जानकारी देने की दृष्टि से यह संस्थान काफी महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सिद्ध होगा। चाहे विभिन्न फसलों की बुवाई, उनमें समय से सही मात्रा में खाद डालना हो, उचित मात्रा में सिंचाई की जानकारी, जल का बेहतर प्रबंधन हो या मिटटी की गुणवत्ता की जाँच, इन सभी के लिए सिंगल विंडो के रूप में किसान कल्याण केंद्र काम करेंगे और निश्चय ही किसानों को खेती के संबंध में नयी जानकारियाँ देंगे।

आज के समय में अन्न उपजाने से भी जरूरी उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके विषय में भी ये केंद्र काफी उपयोगी और सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

कृषि उपज का बेहतर प्रबंधन, उसकी मार्केटिंग एवं किसानों को उपज का बेहतर मूल्य दिलवाना किसी भी सरकार की प्राथमिकता है।

मैं चाहता हूँ कि हमारे देश का किसान विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार के किसान शीघ्र आत्मनिर्भर हों, और देश की इकॉनोमी में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। यदि हमारे भारत के ये महत्वपूर्ण राज्य कृषि में अपनी सकारात्मक भागीदारी निभाएंगे तो निश्चय ही हम एक उन्नत देश बन जायेंगे। दूसरी हरित क्रांति उत्तर प्रदेश के हरे-भरे खेतों से ही होगी, ऐसा मुझे विश्वास है।

किसान भाइयो, यह संतोष का विषय है कि उत्तर प्रदेश शासन ने आपके कल्याण के लिए यह मेगा प्रदर्शनी आयोजित की है। मुझे इस बात का विश्वास है कि किसानों के लिए सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनायें उनके जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध होंगे। साथ ही, इनसे किसानों को नवीन उत्साह और मनोबल प्राप्त होगा और उनके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आयेगी।

मैं यहाँ पधारने और प्रदर्शनी देखने आने वाले सभी किसान जन समूह और भाइयों एवं बहनों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हुए 'अन्नदाता सुखी भवः' के उदघोष के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ।